## फोकस

# घोषणापत्रों के सब्जबाग और राज्यों की असली हालत

**चुनाव नजदीक हैं इसलिए उत्तरप्रदेश में नौकरियां बंट रही हैं और पंजाब में बिजली-पानी को मुफ्त लुटाया जा रहा है। वोटर को रिझाने के लिए आसमान से तारे तोड़ लाने की होड़ मची है। लेकिन जिस सरकारी खजाने के दम पर ये चुनावी वादे किए जा रहे हैं, उसकी असली हालत क्या है ? और इस हालत की कितनी समझ नेतागणों को है ? जब सपा अध्यक्ष से पूछा गया कि वे बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कहां से पैसा लाएंगे तो उनका जवाब था कि, 'भाजपा सरकार मंत्रियों की फौज के चाय-पानी पर जो खर्च कर रही है, वही रकम बेरोजगार युवकों को दे दी जाएगी।' उधर मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि 'नीयत अच्छी हो तो खजाने की बदहाली आड़े नहीं आती।' इनके बरक्स पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल हैं जो कहते हैं कि, 'बेहतर आर्थिक प्रबंध से वादों को पूरा किया जाएगा।' लेकिन वादे निभाना क्या वाकई इतना आसान है ? राज्यों के वित्तीय आंकड़े क्या कहते हैं ? इस बार के फोकस में इन्हीं सवालों को बूझने की कोशिश की गई है।**

## झूठे वादों से पार्टियों की विश्वसनीयता कम होती है


**जे डी अग्रवाल**

निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फाइनेंस

उ.प्र. और पंजाब के चुनावों में वही हो रहा है जो हमेशा देखने को मिलता है। इन प्रदेशों के लोगों को अपने उन सब नेताओं के आजकल दीदार हो रहे हैं, जो ऊंची इमारतों में रहते हैं और कमांडों से घिरे रहते हैं। सभी दल, उनके नेता एवं स्वतंत्र प्रत्याशी उनके लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाने को बेताब हैं। बड़ी रिसर्च के बाद वे वादों की सूची तैयार कर रहे हैं। बड़ी मशक्कत के बाद उनके घोषणापत्र तैयार हुए हैं। कोशिश यह है कि वोटर को सब्जबाग दिखाने में किसी प्रकार की कमी न रह जाए। उनके प्रान्त के पास संसाधन हैं या नहीं, उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, वादों को हकीकत में बदलने का क्या रोडमैप उनके पास है और उसमें किस प्रकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष रुकावटें आने की संभावना है, ये सवाल वे बिलकुल भूल जाते हैं।

पढ़े लिखे लोग यह मानते हैं कि यथार्थ को सामने रख समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उन समस्याओं का हल हर राजनीतिक दल चुनाव से पहले लोगों के सामने पेश करे और फिर चुनाव के बाद उसे पूरा करे। लेकिन राजनीतिज्ञ शायद ऐसा नहीं मानते। ज्यादातर राजनीतिज्ञ ऐसा समझते हैं कि चुनाव आर्थिक या सामाजिक मुद्दों के सहारे नहीं जीते जाते, बल्कि उनको जीतने के लिए लोगों की भावनाओं को उभारना होगा। उस भावुकता को उभारने के लिए आवश्यक है कि उनकी वे सब जरूरतें जिन्होंने उनको बहुत तंग कर रखा है, उनको पूरा करने का वादा किया जाए। ऐसा देखने में भी आया है कि वादों के सहारे बहुत से राजनीतिक दल सत्ता में आए। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में इस पैंतरे को आजमाया और दो रुपए किलो चावल के वादे ने उनको सत्ता प्रदान कर दी। आज भी देशी विदेशी मीडिया चंद्रबाबू नायडू की जयकार करता है, जबकि आंध्र प्रदेश का एक बड़ा इलाका गरीबी और अकाल की चपेट में है। पिछले 2-3 वर्षों में उनके प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। चुनाव के समय उनके वक्तव्यों में, इच्छाशक्ति तथा संकल्प की झलक थी, लेकिन उनके व्यवहार में यह कितनी खरी उभरी, यह एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन उनका सत्ता में आना और सत्ता में आकर बने रहना एक ऐसी मिसाल है जो किसी नेता को हर प्रकार के वादे करने के लिए प्रेरित करती है।

उत्तर प्रदेश के चुनाव में राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति लेकर उतरे हैं। मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह दलितों को 40 हजार नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं और हर परिवार में एक नौकरी चाहते हैं। मुलायम सिंह यादव बेरोजगार युवकों को बेरोजगार भत्ता दिए जाने की बात कह रहे हैं। मायावती पिछड़े वर्गों की मसीहा बन उनका उत्थान करने की बात दोहरा रही है। इसी प्रकार कांग्रेस भी अपने पैकेज में गरीबों, बेरोजगारों व अल्पसंख्यकों को लुभाने का प्रयत्न कर रही है।

लेकिन प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ताक पर नहीं रखा जा सकता। अगर उ प्र के माननीय वित्त मंत्री के 2000-2001 के बजट भाषण पर एक नजर डालें तो उससे साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश भीषण आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा है। आज यह स्थिति अनेक वर्षों की गलत नीतियों तथा बढ़ते जा रहे भ्रष्टाचार का परिणाम है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 1950-51 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय के बराबर थी, लेकिन अब वह प्रति व्यक्ति आय की राष्ट्रीय औसत से बहुत कम रह गई है। विकास की दौड़ में प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। आंकड़ों पर नजर दौड़ाने से पता चलता है कि उ.प्र. की वित्तीय स्थिति भयंकर तौर पर डावाँडोल है। पिछले दशक में उत्तर प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर यानी विकास दर बिहार को छोड़कर सभी प्रदेशों से कम रही। वह न सिर्फ 1980 के दशक से नीचे चली गई, बल्कि देश की औसत विकास दर से भी आधी रह गई। इसी प्रकार राज्य की प्रति व्यक्ति विकास दर भी पिछले दशक में मात्र 1.24 प्रतिशत रही जो बिहार को छोड़कर सबसे नीचे है। उत्तर प्रदेश में 40.85 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं।

बिहार और उड़ीसा के बाद गरीबी का यह अनुपात सबसे अधिक है। साक्षरता में भी उ. प्र. नीचे से तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अपने राजस्व का 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा कर्जों का ब्याज चुकाने पर खर्च कर रहा है। पंजाब प्रदेश के बाद वह देश का सबसे

अधिक ऋणग्रस्त प्रदेश है।

ऐसी दशा में इस प्रकार के वादों का क्या औचित्य है यह बहुत ही अहम और सोचने का विषय है। 1980 के दशक में उ.प्र. की इतनी बुरी स्थिति नहीं थी लेकिन अब वह तीन सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। जब इसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही हो, राज्य का कर्ज बढ़कर उसके सकल घरेलू उत्पाद के 45 प्रतिशत के लगभग हो चुका हो और जब अपने कुल राजस्व के डेढ़ गुना से ज्यादा धन राशि वह अपने कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर खर्च कर रहा हो और जब वह एक चौथाई से अधिक वार्षिक राजस्व ब्याज की अदायगी में लगा रहा हो तो ऐसे भारी भरकम वादों के लिए धन कहां से एकत्रित हो पाएगा, यह सोचने की बात है। उ. प्र. में संसाधनों की कमी नहीं है। राज्य में निर्यात बढ़ाने की क्षमता है। चमड़ा, कालीन, पीतल, हथकरघा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, आईटी, कृषि एवं फूड प्रोसेसिंग को प्रोत्साहन देकर यह प्रदेश आगे बढ़ सकता है। लेकिन कोई भी दल उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण कर एक ऐसी नीति लोगों के सामने पेश नहीं कर रहा है जो यथार्थ के आस पास हो और जो उ प्र एवं उसके नागरिकों में सच्ची आशा जगाए।

### मुलायम उवाच

'भाजपा सरकार ने अपने मंत्रियों की फौज की चाय-पानी पर जो करोड़ों रुपये बहा दिए, वह रकम उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवकों को दी जाएगी। इसलिए बेरोजगार भत्ते के लिए रकम की चिंता नहीं।'

उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को एक समान अवसर मिलें और वे अपना सिर ऊंचा उठा कर यह कहें कि हम उ. प्र. के वासी हैं, यह बहुत जरूरी है। मेरा यह मानना है कि आज उत्तर प्रदेश के लोग प्रदेश की दयनीय आर्थिक स्थिति को समझते हैं।

वित्तीय अनुशासन को अपनाने का महत्व महसूस करते हैं। सार्वजनिक उपकरणों की जैसे विद्युत बोर्ड, जल निगम आदि का ढांचा बदलने की जरूरत को भी स्वीकार करते हैं। लोग यह भी मानते हैं कि सभी सरकारी विभागों में आवश्यकता से कहीं अधिक कर्मचारी हैं और ये सरप्लस कर्मचारी भी दिया गया काम पूरा नहीं करते। इन सब बातों को देखते हुए वे नेताओं के हवाई वादों से खुश होने की बजाय और मायूस ही होते हैं। एक किस्म की वितृष्णा उनके भीतर भर गई है और वे मोहभंग में जी रहे हैं।

पंजाब के चुनाव एक नया ही हाल बता रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की बात कर रही है और 1200 करोड़ रुपए की रेवड़ी बांटने का वादा बार बार दोहरा रही है।

वह गरीबों को 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा भी कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री बादल के नेतृत्व वाला अकाली दल एवं भाजपा गठबंधन पंजाब को जर्मनी जैसी औद्योगिक नगरी बनाने का वादा कर रहा है और किसानों को निःशुल्क बिजली, दलितों को मुफ्त घर देने की बात कर रहा है। पांच वर्ष पहले पंजाब को कैलिफोर्निया बनाने का वादा चुनाव में किया गया था।

लेकिन अब जरा पंजाब की माली हालत पर नजर डालें। पंजाब एक धनी प्रदेश है, यहां के लोग मेहनती हैं। भाखड़ा नांगल की बिजली और सतलुज जैसी नदियों का पानी इस प्रदेश को हरा भरा रखते हैं। पंजाब की साक्षरता दर भारत की औसत साक्षरता दर से थोड़ा अधिक है। इस प्रदेश का गरीबी अनुपात सबसे कम है अर्थात 12 प्रतिशत के लगभग, लेकिन 36000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज से ग्रस्त यह प्रदेश अपने वार्षिक राजस्व का एक तिहाई हिस्सा अपने ऋण के ब्याज के भुगतान में ही खर्च कर देता है। इसलिए इसकी विकास दर भारत की औसत विकास दर से कहीं कम है और नीचे से बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा को छोड़कर चौथे स्थान पर है।

लोकलुभावन कदम राज्यों की वित्तीय स्थिति को किस तरह खस्ताहाल करते हैं, इसकी एक मिसाल उत्तर भारत का सबसे सम्पन्न राज्य पंजाब है। अकाली दल ने सत्ता में आने के लिए राज्य के किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने का वादा किया। हालांकि मुफ्त के चक्कर में किसानों को अपनी जरूरत के मुताबिक बिजली भी नहीं मिल सकी और सरकार के राजस्व को भी भारी नुकसान हुआ। इसी तरह से वहां सरकार ने आतंकवाद के बाद पंजाब में पैदा हुई बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिए कोई कारगर कदम उठाने के बजाए किसानों के कर्ज माफ करने का निर्णय किया। किसानों के कर्ज माफ करने से वह सारा बोझ राज्य के खजाने पर पड़ा, दूसरी तरफ आम जनता की स्थिति भी बेहतर नहीं हुई, क्योंकि असली समस्या तो बेरोजगारी की थी। अगर सरकार बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोई कारगर कदम उठाती तो राज्य के खजाने पर इतना बोझ नहीं पड़ता और बेरोजगारी से भी कुछ निजात पाना संभव हो पाता।

पिछले वर्ष पंजाब के वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण को समाप्त करते हुए कहा था कि पंजाब को ताइवान के नक्शेकदम पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि पंजाब का क्षेत्रफल है 50 हजार वर्ग किलोमीटर एवं ताइवान का 36 हजार वर्ग किलोमीटर। दोनों की जनसंख्या लगभग बराबर है लेकिन ताइवान अमेरिका को हर साल सौ अरब डालर का सामान एक्सपोर्ट करता है जबकि पंजाब केवल एक अरब डालर का निर्यात करता है। काश वित्तमंत्री को आज अपना भाषण याद होता। आज वे खुद चुनाव लड़ रहे हैं और किसान की बिजली माफ करने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ताइवान भी किसानों को मुफ्त बिजली दे कर ही सफल निर्यातक देश बना है, यह सवाल उन्हें खुद से पूछना चाहिए।

क्या ताइवान में भी लोग नहर के पानी के सवाल पर उच्चतम न्यायालय को चुनौती देने की मुद्रा में आ जाते हैं ? बेहतर हो कि बादल और दूसरे दलों के नेता बाकायदा योजना बनाकर पेश करें कि किस तरह वे पांच साल के भीतर राज्य का कर्ज चुकाएंगे। किस तरह वे किसानों को इस हालत में लाएंगे कि वे मुफ्त बिजली के मोहताज ही न रहें।